











# सम्पादकीय

# ਸੈਟਲ ਹੈਲਥ ਕੀ ਚੁਨੌਤੀ

जानें कोरोना और लॉकडाउन का आम जिंदगी पर कैसे पड़ा असर

एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि आत्महत्या के मामलों में 2019 के मुकाबले इस साल 10 फीसदी इजाफा हुआ है। 2020 में आत्महत्या से कुल 153,053 मौतें हुई हैं, जो 1967 के बाद से सबसे ज्यादा है। आत्महत्या करने वाले इन लोगों में सबसे ज्यादा संख्या (24.6 फीसदी) दिहाड़ी पर काम करने वालों की है। लॉकडाउन का सबसे मारक प्रभाव इन्हीं लोगों की आजीविका पर पड़ा था। नैशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ओर से जारी किए गए साल 2020 के दौरान आत्महत्या और दुर्घटना में हुई मौतों के आंकड़े इस लिहाज से भी अहम हैं कि पहली बार इनसे कोरोना के आम लोगों के जीवन और खासकर उनके दिलों-दिमाग पर पड़े असर की पुष्टि होती है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने सामान्य जीवन को जिस तरह से तहस-नहस कर दिया था, उसे देखते हुए यह आम धारणा थी कि कमजोर दिल-दिमाग वाले लोगों के लिए इसे सहन करना खासा मुश्किल रहा होगा। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि आत्महत्या के मामलों में 2019 के मुकाबले इस साल 10 फीसदी इजाफा हुआ है। 2020 में आत्महत्या से कुल 153,053 मौतें हुई हैं, जो 1967 के बाद से सबसे ज्यादा संख्या (24.6 फीसदी) दिहाड़ी पर काम करने वालों की है। लॉकडाउन

परारा था, पह जेव रका दोन न जाननमनरता को जा रहा तो सफदर बढ़ाते हुए दूसरे देशों को सैन्य साजो-सामान निर्यात करने की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। उच्च तकनीक वाली मिसाइलों, अत्यधिक लड़ाकू विमानों और उच्च कोटि के सैन्य उपकरणों को सेना के तीनों अंगों का अहम हिस्सा बनाए जाने के चलते एक और जहां भारत की सैन्य ताकत लगातार बढ़ रही है, वहीं दुश्मन देशों की हर प्रकार की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना भी सशक्त हो रही है। इसी कड़ी में पिछले दिनों भारतीय रक्षा अनुसंधान केन्द्र (डीआरडीओ) ने आकाश मिसाइल के नए अपग्रेड वर्जन 'आकाश प्राइम' का सफल परीक्षण करके सेना को मजबूत बनाने की दिशा में एक और बड़ी सफलता हासिल की। डीआरडीओ द्वारा यह परीक्षण तीव्र गति वाले एक मानवरहित हवाई लक्ष्य को निशाना बनाकर किया गया, जिसे 'आकाश-प्राइम' ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इस अपग्रेड आकाश मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल किए जाने के बाद निःसंदेह सेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 30 दिसम्बर 2020 को कैबिनेट की बैठक में भारत की स्वदेशी आकाश मिसाइलों का निर्यात करने का निन्द्य भी लिया गया था, जिसके बाद अब दुनिया के अन्य देश भी इन मिसाइलों को खरीद सकते हैं। दरअसल ऐसी खबरें आती रही हैं कि फिलीपीस, बेलारूस, मलेशिया, थाईलैंड, यूरॉप, वियतनाम इत्यादि दुनिया के कुछ देश आकाश मिसाइलों की मारक क्षमता से प्रभावित होकर भारत से ये मिसाइलें खरीदना चाहते हैं।

निश्चित रूप से भारत के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो देश जारहां, युग एवरबैंस पर भा आकाश मिसाइल तनात का गइ हा भारत में अभी तक आकाश मिसाइल के कुल तीन रैरिएंट मौजूद थे, जिनमें 30 किलोमीटर रेंज वाली 'आकाश एमके1, 40 किलोमीटर रेंज वाली 'आकाश एमके1एस और 80 किलोमीटर रेंज की 'आकाश-एनजी मिसाइलें शामिल थी। अब चौथा संस्करण 'आकाश प्राइम' भी आकाश मिसाइलों की इस श्रृंखला में जुड़ गया है। आकाश एमके1 और एमके1एस सभी मौसम में कम, मध्यम और ऊर्चाई से प्रवेश करने वाले मध्यम दूरी के हवाई लक्ष्यों के खिलाफ एक बायु रक्षा हथियार प्रणाली (एयर डिफेंस वेपन सिस्टम) है लेकिन आकाश प्राइम मिसाइल को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह ऐसी परिस्थितियों से और भी बेहतर तरीके से निपट सके।

21 जुलाई 2021 को आकाश मिसाइल के अपडेटेड वर्जन 'आकाश-एनजी (आकाश न्यू-जनरेशन)' का भी सफल परीक्षण किया जा चुका है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डीआरडीएल) द्वारा विकसित किया गया और भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) तथा भारत डायोनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। सतह से हवा में मार करने वाली भारतीय बायुसेना के लिए बनाई गई 19 फुट लंबी, 720 किलोग्राम वजनी और 1.16 फुट व्यास वाली आकाश-एनजी मिसाइल अपने साथ 60 किलोग्राम वजन के हवाईयार ले जा सकती है और 20 किलोमीटर की ऊर्चाई तक जाकर करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को भी भेद सकती है। इसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर है। आकाश सीरिज की यह मिसाइल दुश्मन को बचने की तैयारी का ऊर्चाई वाले क्षेत्रों में औसत दैनिक न्यूनतम तापमान होता है। बहरहाल,

का सबसे मारक प्रभाव इन्हीं लोगों की आजीविका पर पड़ा था। लेकिन अगर पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी का प्रतिशत देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित तबके के रूप में उभरते हैं स्टूडेंट्स। अमृमन हर साल खुदकुशी करने वालों में स्टूडेंट्स 7-8 फीसदी होते हैं, लेकिन साल 2020 में इनका प्रतिशत 21.2 दर्ज किया गया है।

अब तक अपनी अधिकांश रक्षा जरूरतें कुछ दूसरे विकसित देशों से आयात करके पूरी करता था, वह अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए दूसरे देशों को सैन्य साजों-सामान निर्यात करने की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। आकाश मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एक मध्यम दूरी की मोबाइल सैम (सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल) प्रणाली है, जो 18 हजार फुट तक की ऊंचाई पर 30-80 किलोमीटर दूर तक कोई अवसर नहीं देती क्योंकि इसकी गति 3.5 मैक्र 3र्थात् 4321 किलोमीटर प्रतिघंटा है यानी यह महज एक सेंकेंड में ही सवा किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस मिसाइल को बनाने की अनुमति वर्ष 2016 में मिली थी, जिसमें दुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर है, जो इसकी गति को बढ़ाती है। इसके अलावा इसमें एक साथ कई दुश्मन मिसाइलों या विमानों को स्कैन करने के लिए एकिटर इलैक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐर मल्टी फंक्शन राडार (एमएफआर) लगा है। डीआरडीओ द्वारा अब सतह से उच्च ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में विश्वसनीय प्रदर्शन

‘सरदार उधम पर फिजूल है यह विवाद, ऑस्कर में फिल्म भेजने को लेकर क्यों उठ रहे सवाल’

ऑस्कर की ‘श्रेष्ठ इंटरनैशनल फीचर फिल्म श्रेणी’ के लिए भारत से तमिल फिल्म ‘कुलगल (झंते)’ भेजी जाएगी। इसका शाब्दिक अर्थ है- कंकड़। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की इस घोषणा के बाद मीडिया और सोशल मीडिया में विरास्त और विवाद चल रहा है। विवाद का कारण निर्णयक समिति के एक सदस्य इंद्रदीप दासगुप्ता का बयान है, जिसमें उन्होंने ‘सरदार उधम’ को न भेजने का कारण बताया है। उनका कहना है, ‘छिसमें ब्रिटिश के खिलाफ हमारी नफरत दिखाई गई है। गोबलाइजेशन के इस दौर में इस नफरत को बनाए रखना सही नहीं है। अधिकांश आलोचकों का मानना है कि इंद्रदीप दास गुप्ता का तर्क अनुचित है और इस आधार पर ‘सरदार उधम’ को ऑस्कर में न भेजना गलत है। यह कहीं न कहीं ‘साप्राज्यवादी हैंगओवर है। वास्तव में दासगुप्ता की कहीं गई बात की संदर्भहीन व्याख्या की जा रही है।’ ब्रिटिश के खिलाफ शब्दों से अधिकांश को यही लगता है कि यह बयान राष्ट्रीय दर्प और एक क्रांतिकारी के योगदान को नजरअंदाज करता है। बहस में निर्णयक समिति के एक और सदस्य सुमित बसु के बयान पर गौर ही नहीं किया गया। इस पर भी बात नहीं हो रही है कि ऑस्कर पुरस्कार में भेजने के लिए चुनी गई तमिल फिल्म ‘कुलगल’ कैसी है। ‘न्यू इंडिया के राष्ट्रवाद लिए धन नहीं रहता। यह राशि अनेक बार फिल्म की लागत से ज्यादा होती है। फिल्म के निर्माता-निर्देशक लगभग साढ़े तीन-चार महीनों के इस अभियान में व्यस्त रहते हैं और नतीजा अभी तक निल बटे सननटा ही आया है। बेशक इंटरनैशनल प्रतियोगिताओं में भारतीय फिल्में भेजी जाने चाहिए, इसी सौच के तहत फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया चुनाव के लिए आई तमाम भाषाओं की फिल्मों में से श्रेष्ठ फिल्म का चुनाव करता है। ध्यान रहे, देश की सभी श्रेष्ठ फिल्मों पर विचार नहीं होता। जो निर्माता इस चुनाव के लिए अपनी फिल्में भेजते हैं, उनमें से ही एक का चुनाव किया जाता है। कई बार बेहतरीन फिल्मों के निर्माता-निर्देशक इसे व्यर्थ का शगल मानकर अपनी फिल्म ही नहीं भेजते।

पिछले सालों में निर्णयक समिति के नियन्यों पर कई बार विवाद हुए हैं, लेकिन पहले किसी निर्णयक की कोई टिप्पणी सुनने को नहीं मिलती थी। इस साल पहली बार दो सदस्यों की संक्षिप्त टिप्पणी सामने आई है। इसमें लोकतांत्रिक पारदर्शिता की झलक तो मिलती है, लेकिन पूरा परिदृश्य सामने नहीं आता। अगर निर्णयक समिति के अध्यक्ष ने सर्वसम्मति से चुनी गई फिल्म ‘कुलगल’ की घोषणा की है तो बहस के दौरान असहमति और विरोध में कहीं गई टिप्पणियों पर बात करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी ही बातें

# कांग्रेस के पुनर्जीवन की पगबाधा

राजेन्द्र शर्मा

सब कुछ के बावजूद चूंकि कांग्रेस ही देश के पैमाने पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसकी यह कमजोरी देश के पैमाने पर किसी विश्वसनीय विकल्प की संभावनाओं को भी कमजोर करती है। इसलिए, सिफ़र कांग्रेस के अपने हित में ही नहीं, देश के हित में भी यह ज़रूरी है कि वह नवउदारवाद की वैकल्पिक नीतियों के मंच की ओर बढ़े। ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने और उसके गिर्द, मेहनतकश़ों के बढ़ते ध्वनीकरण करने इसकी ज़रूरत और संभावनाओं, दोनों को ही गाढ़े रंग से रेखांकित कर दिया है। अचरज की बात नहीं है कि पंजाब सरकार में पिछले ही महीने हुए उलट-फेर पर कई टिप्पणीकारों ने अपनी इस धारणा को दोहराया था कि कांग्रेस, आत्मघात की प्रवृत्ति से ग्रस्त नजर आती है। विधानसभाई चुनाव से चंद महीने पहले, मुख्यमंत्री बदलने और पंजाब में पहली बार एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने के पैतरे से, कांग्रेस पंजाब में अपनी सरकार बचा पाती है या एक और राज्य में सरकार उसके हाथ से निकल जाती है, यह तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन, इतना तो तय है कि इस कदम से कांग्रेस ने, ऐतिहासिक किसान आंदोलन के पृष्ठभूमि में, कम से कम प्रकटतः जीती नजर आती बाजी में, गंभीर अनिश्चितताओं को न्यौत लिया है। इतना ही नहीं, इस उलट-फेर ने जिस तरह से यह कांग्रेस में चैंटगारा अमंत्रितों को तथा गर्जा में गार्मि में दशकों का उत्सुकता आधक हान का वजह यहा ह तक यह फिल्म 16 अक्टूबर को एक ओटीटी प्लैटफॉर्म पर आ चुकी है। दर्शकों ने इसे देख लिया है। समीक्षकों ने भी इस फिल्म की सराहना की है। इसके निर्देशक शूजित सरकार हैं, जो सफल और संवेदनशील फिल्मों के लोकप्रिय निर्देशक हैं। इसके विपरीत 'कुलगंग अभी मुख्य रूप से फैस्टिवल में दिखाई गई है। देश के कुछ सुधी समीक्षकों ने इसे जरूर देखा है, लेकिन आम दर्शकों के बीच यह फिल्म नहीं पहुंची है। यह युवा निर्देशक पीएस विनोदराज की सीमित बजट की छोटी फिल्म है। यह एक शाराबी पति की कहानी है, जो घर से चली गई पतनी की तलाश में अपने सात-आठ वर्षीय बेटे के साथ निकलता है। बदले दौर में इस फिल्म के बाप-बेटे प्रेमचंद की 'कफन' कहानी के धीमू सूझ और माधव की याद दिलाते हैं। अभाव और अवसाद के दृश्यों के बीच भी निर्देशक अपने मुख्य किरदारों के लिए सहानुभूति नहीं पैदा करता। वह स्थितियों के चित्रण से मनुष्य की प्रकृति जाहिर करता है। निर्णायक समिति के अध्यक्ष शाजी एन करुण ने इस फिल्म की धोषणा के समय कहा है कि 'हम ऐसी फिल्म चुन कर भेज रहे हैं, जिसके नामांकन और पुरस्कृत होने की सर्वाधिक संभावना है। सिनेमाई कॅट्टे के साथ इसकी गुणवत्ता पुरस्कार के योग्य है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं है। हमें ऐसी फिल्म चुननी थी, जो 92 देशों की फिल्मों के बीच ध्यान खींचे। ऑस्कर

जिस तरह से खुद कांग्रेस में चारतरफा असंताप का तथा राज्य में पाठी में एक गंभीर व सभावित रूप से घातक विभाजन को भड़काया है, उसे देखते हुए यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कांग्रेस का प्रभावी नेतृत्व, संगठन को संभालने के मामले में एकदम अनाड़ी साबित हो रहा है। इस सब के ऊपर से, पंजाब की हाल की उथल-पुथल ने, जिस तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ की दोनों अन्य कांग्रेसी सरकारों में अंदरूनी उठा-पटक तथा खींच-तान को नये सिरे से हवा दे दी, वह भी कांग्रेस नेतृत्व की चुनौतियों को ही नहीं, विफलताओं को भी दिखाता है।

अचरज नहीं कि इस संकट के साथ ही, जी-23 कहलाने वाला, कांग्रेस नेताओं का वह रूप भी फिर से हरकत में आ गया, जिसने पिछले साल सामूहिक रूप से एक पत्र लिखकर, कांग्रेस के प्रभावी नेतृत्व की कार्य-पदधित पर कई सवाल उठाए थे। इस सब के साथ अगर हम मिसाल के तौर पर गोवा में कांग्रेस में बड़ी टट्ट को और जोड़ लें तो, एक भारा भूल होगा। यह समझना मुश्किल नहा है कि कांग्रेस आज जन समस्याओं का सामना कर रही है, उनका संबंध उसके नेतृत्व तथा संगठन की कमज़ोरियों से उतना नहीं है, जितना उसके जनाधार के घटने और उसके सत्ता से दूर से दूर खिसकते जाने से है। शासक वर्ग से जुड़ी पार्टी के नाते, एक पार्टी के रूप में ही नहीं बल्कि नेतृत्व के साथ भी जो गेंद कांग्रेसियों को चिपकाए रहता था, वह सत्ता से दूरी की इस धूप में सूखता जा रहा है। ऐसे में नेतृत्व से कुछ जायज तो ज्यादा झूटी शिकायतों समेत, तरह-तरह के बहानों से, बिखराव का सिलसिला बढ़ाता जा रहा है। इस संदर्भ में सिंधिया, पायलट, सुष्मिता देब, जतिन प्रसाद आदि आदि, राहुल गांधी के नजदीकी माने जाने वाले, अपेक्षाकृत युवा नेताओं का कांग्रेस से अलग होना, विशेष रूप से अर्थपूर्ण है, जिसने कांग्रेस पार्टी के ढांचे को जनतांत्रिक बनाने के राहुल गांधी के बहुचर्चित मिशन को, जो अपनी सारी नेकनीयती के बावजूद, काफी हृद तक लिए उसे मदद चाहिए, वह भी अपनी शर्तों पर। अफगानिस्तान के हालात को लेकर दुनिया भर के देश चित्तित हैं। सब चाहते हैं कि

निराकार के तार पर गांव न कांग्रेस न बड़ा दूर पर जा जाए छोड़ दा, एक कमोबेश बिखरती हुई पार्टी की ही तस्वीर नजर आती है। इस सब को देखते हुए, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में सब कुछ ठीक होना तो दूर, संकट ही संकट है। जाहिर हैं कि 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए, राहुल गांधी के खासतौर पर युवाओं के संगठनों के नेतृत्व के लिए जनतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने पर आपत्तियां भी शामिल थीं। कहने का आशय यह कि सत्ता से दूरी के चलते कांग्रेस में बढ़ते बिखराव को, जनतांत्रिक चुनाव या युवतर नेतृत्व को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता ने, उसकी समस्याएं बढ़ाने की काम किया है।

बेशक, इस सब की पृष्ठभूमि में और ज्ञात असंतुष्टों के बार-बार मांग करने के बाद बुलाई गई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में, एक ओर श्रीमती सोनिया गांधी के जोर देकर इसकी याद दिलाने कि 'वह पूर्णकालिक अध्यक्ष' है और पार्टी में चुनाव के अगले साल भर चलने वाले कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के बाद, असंतोष कुछ थमा जरूर है। लेकिन, इसे कांग्रेस के लिए अस्थायी राहत से ज्यादा नहीं माना जा सकता है। वास्तव में अगले साल के शुरू में होने जा रहे विधानसभाई चुनावों के बाद, राहुल गांधी के दोबारा अध्यक्ष पद संभलने से भी, जिसकी काफी संभावनाएं नजर आती हैं, कांग्रेस के संकट का कोई टिकाऊ हल निकल आएगा, यह मानना मुश्किल है। तो क्या यह समझा जाना चाहिए कि कांग्रेस का वर्तमान संकट केवल या मुख्यतः उसके वर्तमान नेतृत्व की और उसमें भी खासतौर पर "गांधी परिवार" परिवार कहलाने वाले नेतृत्व कुल की, सीमाओं-विफलताओं का ही नतीजा है। इतिहासकार ऐसा मानने वाले बहिर्जीवियों की संख्या भी कम नहीं है। इतिहासकार अफगानिस्तान में विकास हो। बाकी जनता को समस्याएं हल हो। लोगों को भरण-पोषण की चौंज उपलब्ध हो। पर अफगानिस्तान पर काबिज अपने एजेंट्से से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसका क्रूरता का चेहरा वैसा ही है जैसा बीस साल पहले था। उसने उसपर कोई मुख्योंता नहीं लगाया। कोई आवरण नहीं ओढ़ा। उनको दुनिया से अपने लिए मदद चाहिए, वह भी अपनी शर्तों पर। उन्हें न मानवता से कुछ लेना है, न मानव समाज से अभी रुस ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर की मेजबानी की इसमें तालिबान प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने भी बात की। भारत ने सहायता का आश्वासन भी दिया। चीन ने युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान को 10 लाख अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराए हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि चीन ने यह आर्थिक मदद दी है और मानवीय मदद (विशेष रूप से भोजन और दवाओं के लिए) के तौर पर पांच लाख अमेरिकी डॉलर और उपलब्ध कराने का बादा भी किया है। अफगानिस्तान की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। वहां भोजन का संकट है। पेट भरने के लिए लोग अपनी बेटियां तक बेच रहे हैं। वहां न जरूरत का समान है, न ठंड से बचने के लिए कपड़े। इस हालत से दुनिया अफगानिस्तान की जनता के बारे में सोच रही है। चिंताकर रही है। किंतु अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान का रवैया कुछ और ही कहता है। उनके आचरण से लगता है कि पिछले 20 साल में उन्होंने अपने में कोई बदलाव नहीं किया। उनका एजेंडा वही है। वे कट्टर इस्लामवाद से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। सत्ता पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने मान्यता पाने के लिए सभी धर्मी को साथ लेकर चलने का दावा किया था। लेकिन अब अल्पसंख्यकों के लिए वहां सुरक्षा हालात बद से बदरत होते जा रहे हैं। तालिबान ने वहां रहने वाले सिखों को फरमान जारी करते हुए कहा है कि या तो इस्लाम कुबूल कर लो या फिर देश छोड़ दो। इतना ही नहीं इस्लाम कबूल न करने पर जान से मारने की धमकी दी जारी है। तालिबान ने सत्ता संभालते ही जेल में बंद सभी कैदियों को रिहाकर दिया। अब ये रिहा कैदी उन्हें सजा देने वाले न्यायधीश को खोज रहे हैं। न्यायधीश अपनी जान बचाते घूम रह है। अफगानिस्तान से भागी 26 महिला जज ग्रीस में शरण लिए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद लगा था कि चीन पाकिस्तान और रुस तथा आसपास के कुछ इस्लामिक कंट्री उसे तुरंत मान्यता दे देंगे। पाकिस्तान तो इस अभियान के लिए सक्रिय भी हुआ। इतना सब होने के दो माह बाद भी अब तक एक भी देश तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दे सका। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि अमेरिका से वार्ता में उसने वायदा किया था कि वह देश में मौजूद सभी संगठनों को साथ लेकर सरकार बनाएगा। अफगानिस्तान से सटे देश चाहते हैं कि अफगानिस्तान में शांति रहे। वहां की जनता को जरूरत की चौंज आराम से मिलती रहे, किंतु यह सब आपके -मेरे चाहने और सोचने से होने वाला नहीं है। उसके लिए तो तालिबान को ही अपने रवैये में परिवर्तन करना होगा। उसे ही अपने को इस योग्य बनाना होगा कि दुनिया स्वयं सहायता के लिए आगे आए।

**नवी बृद्धा वालिहानि सिंहतों को शार्दूलने का प्रयास**

अफगानिस्तान के कब्जे के दो माह बाद भी तालिबान का रवैया वही है, जो बीस साल पहले था। खस्ता हाल और भूखे देश को चलाने के लिए उसे मदद चाहिए, वह भी अपनी शर्तों पर। अफगानिस्तान के हालात को लेकर दुनिया भर के देश चिंतित हैं। सब चाहते हैं कि अफगानिस्तान में विकास हो। बाकी जनता की समस्याएं हल हो। हालात सामान्य हो। लोगों को भरण-पोषण की चीजें उपलब्ध हों। पर अफगानिस्तान पर काबिज अपने एजेंडे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसका क्रूरता का चेहरा बैसा ही है जैसा बीस साल पहले था। उसने उसपर कोई मुखौटा नहीं लगाया। कोई आवरण नहीं ओढ़ा। उनको दुनिया से अपने लिए मदद चाहिए, वह भी अपनी शर्तों पर। उन्हें न मानवता से कुछ लेना है, न मानव समाज से अभी रुस ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर की मेजबानी की इसमें तालिबान प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने भी बात की। भारत ने सहायता का आश्वासन भी दिया। चीन ने युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान को 10 लाख अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराए हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि चीन ने यह आर्थिक मदद दी है और मानवीय मदद (विशेष रूप से भोजन और दगाओं के लिए) के तौर पर पांच लाख अमेरिकी डॉलर और उपलब्ध कराने का वादा भी किया है। अफगानिस्तान की आर्थिक हालात ठीक नहीं है। वहां भोजन का संकट है। पेट भरने के लिए लोग अपनी बेटियां तक बेच रहे हैं। वहां न जरूरत का समान है, न ठंड से बचने के लिए कपड़े। इस हालात से दुनिया अफगानिस्तान की जनता के बारे में सोच रही है। चिंताकर रही है। किंतु अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान का रवैया कुछ और ही कहता है। उनके आचरण से लगता है कि पिछले 20 साल में उन्होंने अपने में कोई बदलाव नहीं किया। उनका एजेंडा रही है। वे कट्टर इस्लामवाद से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। सत्ता पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने मान्यता पाने के लिए सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का दावा किया था। लेकिन अब अल्पसंख्यकों के लिए वहां सुरक्षा हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तालिबान ने वहां रहने वाले सिखों को फरमान जारी करते हुए कहा है कि या तो इस्लाम कुबूल कर लो या फिर देश छोड़ दो। इतना ही नहीं इस्लाम कबूल न करने पर जान से मारने की धमकी दी जारी है। तालिबान ने सत्ता सभालते ही जेल में बंद सभी कैदियों को रिहाकर दिया। अब ये रिहा कैदी उन्हें सजा देने वाले न्यायधीश को खोज रहे हैं। न्यायधीश अपनी जान बचाते घूम रहे हैं। अफगानिस्तान से भागी 26 महिल जज ग्रीस में शरण लिए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद लगा था कि चीन पाकिस्तान और रुस तथा आसपास के कुछ इस्लामिक कंट्री उसे तुरंत मान्यता दे देंगे। पाकिस्तान तो इस अभियान के लिए सक्रिय भी हुआ। इतना सब होने के दो माह बाद भी अब तक एक भी देश तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दे सका। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि अमेरिका से वार्ता में उसने वायदा किया था कि वह देश में मौजूद सभी संगठनों को साथ लेकर सरकार बनाएगा। अफगानिस्तान से सटे देश वाहते हैं कि अफगानिस्तान में शांति रहे। वहां की जनता को जरूरत की चीज आराम से मिलती रहे, किंतु यह सब आपके मेरे चाहने और सोचने से होने वाला नहीं है। उसके लिए तो तालिबान को ही अपने रवैये में परिवर्तन करना होगा। उसे ही अपने को इस योग्य बनाना होगा कि दुनिया स्वयं सहायता के लिए आगे आए।



